



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1989/चैत्र 10, 1911
No. 182] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1989/CHAITRA 10, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1989

का.पा. 248(अ)/18कह/आई.डी.आर.ए./89--केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का.पा. 134(अ)/18कह/आई.डी.आर.ए./79, तारीख 13 मार्च, 1979 द्वारा तथा उपस्थित आदेश सं. का.पा. 529(अ)/18कह/आई.डी.आर.ए./74 तारीख 6 सितम्बर, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) गवियर, बंद एवं कृष्ण उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है मैमर्न इंडिया बैल्टिंग एण्ड काटन

मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर, पश्चिम बंगाल का (जिसे इस वक्त परबाँधे उत्तम औद्योगिक उत्पन्न किया गया है) तारीख 6 नवम्बर, 1974 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रयोज्य प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया था।

और केंद्रीय सरकार की यह राय थी कि जोहूरि में यह योजनाओं के लिए उत्तम प्रयोज्य अवधि को उपर्युक्त पाँच वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रमाणों बना रहना चाहिए और उक्त 31 मार्च, 1989 तक की, जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, अतिरिक्त अवधि के लिए इन योजनाओं के लिए समस्त-वस्तु पर निर्धारण जारी किए थे, (देखिये भारत सरकार, उद्योग विभाग, आर्थिक विभाग विभाग के माध्यम)

सं. का.आ. 512(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./79, तारीख 4 नवम्बर, 1979

सं. का.आ. 749(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./80, तारीख 5 नवम्बर, 1980

सं. का.आ. 684(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./81, तारीख 1 नवम्बर, 1981

सं. का.आ. 125(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 5 मार्च, 1982

सं. का.आ. 648(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 4 नवम्बर, 1982

सं. का.आ. 158(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 4 मार्च, 1983

सं. का.आ. 386(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 31 मार्च, 1983

सं. का.आ. 937(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 29 नवम्बर, 1983

सं. का.आ. 170(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./84, तारीख 28 जून, 1984

सं. का.आ. 947(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./84, तारीख 18 नवम्बर, 1984

सं. का.आ. 257(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./85, तारीख 28 मार्च, 1985

सं. का.आ. 119(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./86, तारीख 27 मार्च, 1986

सं. का.आ. 268(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./87, तारीख 30 मार्च, 1987 तथा

सं. का.आ. 325(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./88, तारीख 30 मार्च, 1988।

और केंद्रीय सरकार को यह है कि जोहूरि में इस योजनाओं के लिए उत्तम औद्योगिक उत्पन्न का अवधि उक्त प्राधिकृत अवधि द्वारा 31 मार्च, 1990 तक का और अवधि के लिए बना रहेगा,

अतः केंद्रीय सरकार उद्योग (विभाग और विदेशी) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उद्धार (2) द्वारा प्रत्येक अवधि के लिए बना रहेगा, यह विभाग से है कि उक्त प्राधिकृत 31 मार्च, 1990 तक अवधि यह तारीख को सम्मिलित है, को और अवधि के लिए प्रमाणों बना रहेगा।

[का. सं. 2(14)/80-सी यू एन]

आर. के. मिन्हा, संयुक्त सचिव

 MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1989

S.O. 248(E)/18AA/IDRA/39. —Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)/18AA/IDRA/74, dated the 6th September, 1974 as modified by the order No. S.O. 134(E)/18AA/IDRA/79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messers India Belating and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of five years from the 6th September, 1974;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1989 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development)).

Nos. S.O. 512(E)/18AA/IDRA/79, dated the 4th September, 1979,

S.O. 749(E)/18AA/IDRA/80, dated the 5th September, 1980,

S.O. 684(E)/18AA/IDRA/81, dated the 4th September, 1981,

S.O. 125(E)/18AA/IDRA/82, dated the 5th March, 1982,

S.O. 648(E)/18AA/IDRA/82, dated the 4th September, 1982,

S.O. 158(E)/18AA/IDRA/33, dated the 4th March, 1983,

S.O. 335(E)/18AA/IDRA/33, dated the 31st May, 1983,

S.O. 937(E)/18AA/IDRA/33, dated the 29th December, 1983,

S.O. 471(E)/18AA/IDRA/84, dated the 28th June, 1984,

S.O. 947(E)/18AA/IDRA/34, dated the 18th December, 1984,

S.O. 257(E)/18AA/IDRA/85, dated the 28th March, 1985,

S.O. 119(E)/18AA/IDRA/86, dated the 27th March, 1986,

S.O. 268(E)/18AA/IDRA/87, dated the 30th March, 1987, and

S.O. 325(E)/18AA/IDRA/88 dated the 30th March, 1988.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for a further period upto 31st March, 1990.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1990.

[File No. 2(14)/80-CUS]

R.K. SINHA, Jt. Secy.